जनसंख्या-वृद्धि : आर्थिक विकास में सहायक
(Population Growth : Conducive to Economic Development)

जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है, इस विचार को मानने वालों में प्रो. हैन्सन, एडम स्मिथ, आर्थर लुईस, कोलिन क्लार्क, पेनरोज, हर्षमैन, बुशकीन तथा अल्फ्रेड बोन (Alfred Bonne) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। **प्रो. हेन्सन** (Alvin Hansen) के अनुसार, "जनसंख्या-वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व-शर्त है।" **प्रो. हर्षमैन** (A. O. Hirschman) का कहना है कि "जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।" बढ़ती हुई जनसंख्या बाजारों का विस्तार करती है जिससे निवेश-प्रेरणा को बल मिलता है। फलत: उत्पादन तथा रोजगार बढ़ने लगता है। अत: जनसंख्या-वृद्धि किसी देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, इस सम्बन्ध में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं :

(1) **श्रम-शक्ति-आपूर्ति का स्रोत** (Source of Working Labour Force)—आर्थिक विकास प्राकृतिक साधनों, श्रम-शक्ति, पूँजी तथा तकनीक का फलन है। इनमें से श्रम-शक्ति सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि विकास प्रक्रिया में वही एकमात्र प्रावैगिक साधन है। **साइमन कुजनेट्स** (Simon Kuznets) के अनुसार, "अन्य बातें समान रहने पर जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि श्रम-शक्ति को बढ़ाती है।" किसी देश की कार्यकारी श्रम-शक्ति विकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं सक्रिय घटक है और इस श्रम-शक्ति की आपूर्ति का स्रोत जनसंख्या है। इस प्रकार कार्यकारी श्रम-शक्ति की पूर्ति के स्रोत के रूप में, जनसंख्या-वृद्धि आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है और इसका प्रभाव अन्तत: उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने का होता है।

(2) **बाजारों का विस्तार** (Expansion of Markets)—किसी देश की जनसंख्या वृद्धि से श्रम-शक्ति की आपूर्ति होती है। इस दृष्टि से श्रम उत्पादक है किन्तु जनसंख्या वृद्धि से उपभोग भी बढ़ जाता है। जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन भी है तो साध्य भी अर्थात् लोग केवल धन के उत्पादक ही नहीं होते बल्कि धन का उपभोग भी करते हैं। पूरकता के इस अर्थ में, जनसंख्या-वृद्धि उपभोक्ताओं के रूप में वस्तुओं के लिए माँग पैदा करती है। इस तरह बाजारों का विस्तार → बचतों में वृद्धि → पूँजी निवेश में वृद्धि → उत्पादन के ढाँचे में विविधता → नये उद्योगों को बढ़ावा → रोजगार के अवसर में वृद्धि → लोगों की आय में वृद्धि → अतिरिक्त माँग में वृद्धि → उत्पादन व आय में वृद्धि → आर्थिक संवृद्धि। इस प्रकार जनसंख्या-वृद्धि वस्तुओं की अतिरिक्त माँग का सृजन करके आर्थिक विकास को बल प्रदान करती है।

(3) **उत्पादन में वृद्धि** (Increase in Production)—यदि किसी देश की जनसंख्या-वृद्धि 1 प्रतिशत वार्षिक या इससे कम है तो जनसंख्या में यह धीमा प्रतिस्थापन उत्पादन एवं विकास की दृष्टि में सहायक है किन्तु यदि यह प्रतिस्थापन वार्षिक 2 प्रतिशत या इससे अधिक है तो जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि उत्पादन एवं विकास की दृष्टि में बाधक है।[2] **डॉ. ब्राइट सिंह** का भी मत है कि "जनसंख्या वृद्धि गहन श्रम-विभाजन तथा व्यापक विशिष्टीकरण को जन्म देती है, पैमाने की बचतों को सम्भव बनाती है जिससे तकनीकी प्रगति तथा संगठनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिलता है।"

(4) **पूँजी-निर्माण का स्रोत** (Source of Capital Formation)—**रागनर नर्कसे** (Ragner Nurkse) का मत है कि अतिरिक्त श्रम-शक्ति एक प्रकार की **अदृश्य बचत** (Disguised Savings) है और अर्द्ध-बेरोजगारी के रूप में इन अदृश्य सम्भाव्य बचतों को पूँजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

किसी देश में भौतिक पूँजी का निर्माण मानव-पूँजी के निर्माण पर निर्भर करता है और मानव-पूँजी का निर्माण प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम-शक्ति पर निर्भर करता है। अत: जनसंख्या वृद्धि → सृजनात्मक मस्तिष्कों का सृजन → मानव पूँजी का निर्माण → परीक्षित ज्ञान (Tested Knowledge) में वृद्धि → आर्थिक संवृद्धि व विकास।

(5) **कौशल-निर्माण को बढ़ावा** (Promotes Skill Formation)—**साइमन कुजनेट्स** के अनुसार, "आर्थिक उत्पादन की वृद्धि, परीक्षित ज्ञान (Tested Knowledge) के स्टोर का फलन है।" नये ज्ञान की खोज व उसका विकास मानव द्वारा किया जाता है जो स्वयं जनसंख्या का परिणाम है। इस प्रकार वृद्धिशील

1 Gupta, S. N., *'Demographic Process in India'*, Hindi Edi. 2002, p. 11.
2 *World Development Report*, 1984, p. 79.

Scanned with CamScanner

जनसंख्या, सृजनात्मक मस्तिष्कों का सृजन करती है जिससे कौशल-निर्माण को बल मिलता है, नये ज्ञान का भण्डार बढ़ता है और फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने लगता है।

जनसंख्या-वृद्धि : आर्थिक विकास में बाधक
(Population Growth : A Retarding Factor to Economic Development)

प्रो. सिंगर (Singer) का कहना है कि "जनसंख्या-वृद्धि आर्थिक विकास की दर पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है, बचत-दर को घटाती है और विनियोग की उत्पादकता को कम करती है।" **डेविस रॉक फैलर** (David Rock Feller) के अनुसार, "अति जनसंख्या वृद्धि आर्थिक संवृद्धि की समस्याओं में से एक सबसे कठिन समस्या है।"[1] इस प्रकार राष्ट्रीय संसाधन पूँजी-निर्माण में न जाकर जनसंख्या-निर्माण में स्वाहा हो जाते हैं। इस विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्री हैं—**माल्थस, नवमाल्थसवादी, हर्षमैन, मायर, सिंगर, नेल्सन** एवं **लाइबेन्सटीन** आदि। जनसंख्या-वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक (गतिरोधक) है, इस सम्बन्ध में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं :

(1) **अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की प्रकृति** (Nature of Under-developed Economy)—अल्प-विकसित अर्थव्यवस्थाएँ विकसित देशों की तुलना में सर्वथा भिन्न परिस्थितियों वाली होती हैं। ये देश दरिद्र, पूँजी-दुर्लभ तथा श्रमाधिक्य वाले होते हैं। पूँजी-निर्माण की समस्या इन देशों की प्रमुख समस्या होती है। अत: पूँजी के अभाव और जनसंख्या के दबाव से असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है जो आर्थिक विकास के लिए मुख्य बाधा है। **प्रो. हर्षमैन** (Hirshman) के अनुसार, "जनसंख्या का दबाव विकास के लिए एक बेढंगा और निष्ठुर प्रोत्साहन है।"

(2) **खाद्यान्न-पूर्ति की समस्या** (Problem of Foodgrain Supply)—अल्पविकसित देशों में तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्यान्न-पूर्ति की कमी की समस्या को जन्म देती है। यह समस्या आर्थिक विकास को तीन रूपों में प्रभावित करती है। **प्रथम,** खाद्यान्न का सम्भरण अपर्याप्त होने पर जनसंख्या का अल्पपोषण होता है जिससे कार्यकुशलता तथा उत्पादन क्षमता घटती है और इसका दुष्परिणाम निम्न प्रति व्यक्ति उत्पादन और गरीबी के रूप में सामने आता है। **द्वितीय,** खाद्य-सामग्री की कमी के कारण, अल्पविकसित देशों को खाद्यान्न आदि का विदेशों से आयात करना पड़ता है जो भुगतान सन्तुलन पर अधिक दबाव डालकर विदेशी विनिमय संकट (Foreign Exchange Crisis) को और भी अधिक बढ़ा देता है। **तृतीय,** विदेशी विनिमय का सही उपयोग न हो पाना, जनसंख्या के अत्यधिक दबाव का तीसरा दुष्परिणाम है।

(3) **प्रति व्यक्ति आय पर अधोगामी प्रभाव** (Regressive Effect on National Income)—व्यष्टि स्तर (Micro Level) पर प्रति व्यक्ति आय किसी देश के आर्थिक विकास (जीवन-स्तर) को परिभाषित करने हेतु सूचकांक का कार्य करती है।[2] तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रति-व्यक्ति आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित स्तर तक जनसंख्या-वृद्धि प्रति-व्यक्ति आय को बढ़ाती है लेकिन उसके बाद वह उसे आवश्यक रूप से कम करती है। **लीबिन्सटीन** (Harve Leibenstien) का भी कहना है कि "जनसंख्या एक दीर्घकालीन कारक होते हुए भी अल्पकाल में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है क्योंकि वह प्रति-व्यक्ति आय की वर्तमान दर के निर्धारक का कार्य करती है अर्थात् उसकी वर्द्धमान प्रवृत्ति प्रति व्यक्ति आय को नीचा बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होती है।"

(4) **पूँजी-निर्माण का कम होना** (Decrease in Capital Formation)—**प्रो. स्पैंगलर** (J. J. Spenglar) के अनुसार औद्योगिक देशों में प्रति 3 श्रमिकों के पीछे 2 व्यक्ति आश्रित होते हैं, जबकि अल्प-विकसित देशों में यह अनुपात 3 : 4 का है। आश्रितों का यह ऊँचा अनुपात बचत करने की क्षमता को घटाता है जिससे पूँजी-निर्माण कम होता है।[3] फिर इन देशों में शिशु मृत्यु-दर ऊँची होती है जिसके कारण उनके पोषण पर साधनों का एक बहुत बड़ा अपव्यय हो जाता है। **प्रो. मायर** (A. M. Meier) के अनुसार, "अल्पविकसित देशों में आश्रितों का ऊँचा अनुपात राष्ट्रीय साधनों के एक बड़े भाग को, जो अन्यथा पूँजी-निर्माण में गया होता, उन आश्रितों के भरण-पोषण की ओर ले जाता है जो कभी भी उत्पादक नहीं बन पाते।"

---

1 "Excessive growth in population is one of the most difficult problems of economic growth."
—*David Rock Feller*

2 शिवनारायन गुप्त : **भारत में जनांकिकीय प्रक्रिया**, पृ. 10।

3 Singh, S. P., '*Economic Development & Planning*' Hindi Edi., (1994), p. 284.

Scanned with CamScanner

(5) **रहन-सहन का नीचा स्तर** (Low Level of Living)—प्रत्येक देश आर्थिक विकास प्रक्रिया को तेज करके अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा बनाने में लगा हुआ है किन्तु ऐसे अल्पविकसित देश जिनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहाँ खाद्यान्न उत्पादन में कमी, आधारभूत उद्योगों का अभाव, शिक्षा-स्वास्थ्य का नीचा स्तर, बेरोजगारी की समस्या जैसी कठिनाइयों के व्याप्त होने के कारण लोगों का रहन-सहन का स्तर (जीवन-स्तर) आज भी नीचा बना हुआ है। इसका ज्वलन्त उदाहरण भारत जैसा विकासशील देश है।

(6) **बेरोजगारी में वृद्धि** (Increase in Unemployment)—जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से श्रम-शक्ति में वृद्धि हो जाती है जिससे बेरोजगारी की सम्भावना बढ़ जाती है।

अल्पविकसित व विकासशील देशों में यदि अल्प रोजगार मुख्य लक्षण है तो अदृश्य (छिपी) बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी इन देशों की मुख्य समस्याएँ हैं। बेरोजगारी की ये दशाएँ अल्पविकसित देशों में कुपोषण, दरिद्रता एवं घुटन को बढ़ावा देती हैं। **प्रो. विलार्ड** के अनुसार, "कम विकसित देशों में धीमी विकास दर और बेरोजगारी का मुख्य कारण श्रम-साधनों की, उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में बाहुल्यता है।"

(7) **देश का असन्तुलित विकास** (Unbalanced Growth)—तीव्र जनसंख्या वृद्धि से अल्पविकसित देश का विकास असन्तुलित ढंग से होता है क्योंकि जनसंख्या में होने वाली अधिकांश वृद्धि को अन्ततः कृषि-क्षेत्र में ही खपाना पड़ता है। अल्पविकसित देशों में चूँकि पूँजीगत साधनों का अभाव होता है, इसलिए इस अतिरिक्त जन-वृद्धि को निर्माणकारी उद्योगों में खपाना सम्भव नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप भूमि पर बढ़ता हुआ और कृषि में उत्पादकता व प्रति-व्यक्ति आय को कम करके, देश के विकास को अवरुद्ध व असन्तुलित बना देता है।

Scanned with CamScanner